मोदी सरकार के 11 साल इन 11 बड़ी योजनाओं ने बदल दी आम आदमी की जिंदगी!

विषय सूची (Table of Contents):

>> आर्थिक समावेशन और सामाजिक सुरक्षा जनधन खाता, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना ...
>> पीएम जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojana)...
>> पीएम सड़क सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana)...
>> पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)...
>> हर सिर को छत और बुजुर्गों को संबल पीएम आवास योजना और अटल पेंशन योजना की जमीनी ह...
>> पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)...
>> अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)...
>> महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्रांति धुएं से आजादी देती उज्ज्वला और संजीवनी बनी...
>> पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana)...
>> आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana)...
>> अन्नदाता को सीधी आर्थिक मदद जानिए कैसे पीएम किसान सम्मान निधि बनी भारतीय कृषि क...
>> पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi)...
>> संकट में बना सहारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्...
>> पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)...
>> हुनर को सम्मान और आत्मनिर्भरता पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजल...
>> पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)...
>> पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana)...
>> निष्कर्ष 11 वर्षों के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं का बढ़ता इरादा और भविष्य ...
>> जनता के सवाल (FAQs)...

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था के इतिहास में पिछले 11 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। 17 सितंबर 1950 को जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभालते ही लोक कल्याणकारी नीतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।

इन 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल गवर्नेंस और सामाजिक सुरक्षा तक, हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं। पीएम जनधन योजना से लेकर मुफ्त इलाज की आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी पहलों ने देश के करोड़ों आम नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कामयाबी हासिल की है।

यदि आप विभिन्न राज्य स्तरीय पहलों के बारे में जानना चाहते हैं, तोयोगी सरकार का बड़ा ऐलान! गरीबों को मिलेगा 7 योजनाओं का सीधा लाभलिंक पर क्लिक कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं मोदी सरकार की उन 11 बड़ी योजनाओं के

बारे में जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी।

आर्थिक समावेशन और सामाजिक सुरक्षा: जनधन खाता, जीवन ज्योति और

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि देश के हर नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उन्हें न्यूनतम प्रीमियम पर सुरक्षा कवच प्रदान करना था। इसने देश में डिजिटल क्रांति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की नींव रखी।

पीएम जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojana)

देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के उद्देश्य से28 अगस्त 2014को इस ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शून्य बैलेंस (Zero Balance) वाले खाते खोले जाते हैं। खाताधारकों को मुफ्त में रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) दिया जाता है, जिससे डिजिटल लेनदेन सुगम हुआ है।

>> लेटेस्ट अपडेट (Latest Update):इस योजना के अंतर्गत अब तक देश भर में 56.38 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं।

>> विशेष लाभ:जनधन खाताधारकों को विपरीत परिस्थितियों में 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा भी प्रदान की जाती है।

पीएम सड़क सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana)

केंद्र सरकार द्वारा इस जनकल्याणकारी योजना की शुरुआत9 मई 2015को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसमें 18 से 70 वर्ष तक की आयु के भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं।

>> बीमा कवर राशि:आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर लाभार्थी के परिवार को 2 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम मिलता है।

>> आंशिक विकलांगता:दुर्घटना में आंशिक रूप से अपंग होने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक का कवर देने का प्रावधान है।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (PM Jeevan Jyoti Bima Yojana)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में9 मई 2015को ही इस टर्म इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया गया था। इस योजना के दायरे में 18 से 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति आते हैं। किसी भी कारणवश पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उसके नामांकित

व्यक्ति (Nominee) को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है, जो गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है।

हर सिर को छत और बुजुर्गों को संबल: पीएम आवास योजना और अटल पे

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। मोदी सरकार ने न सिर्फ बेघरों को पक्का मकान देने का संकल्प लिया, बल्कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बुढ़ापे को भी सुरक्षित करने का काम किया है।

पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)

देश के बेघर और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब नागरिकों को खुद का पक्का घर देने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने25 जून 2015को पीएम आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करोड़ों पक्के मकानों का निर्माण कर लाभार्थियों को सौंपा गया है।

>> समय सीमा का विस्तार:योजना की अभूतपूर्व सफलता और जन-आकांक्षाओं को देखते हुए सरकार ने इसका विस्तार वर्ष 2029 तक कर दिया है, ताकि कोई भी गरीब पक्के मकान से वंचित न रहे।

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)

देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए9 मई 2015को अटल पेंशन योजना (APY) शुरू की गई थी।

>> पात्रता आयु:18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अपना पेंशन खाता खोल सकता है।

>> पेंशन की राशि:लाभार्थी द्वारा किए गए नियमित योगदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह तक की नियमित पेंशन दी जाती है।

महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य क्रांति: धुएं से आजादी देती उज्

महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और देश के गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च से मुक्ति दिलाना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रहा है। इन योजनाओं ने देश के स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है।

पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana)

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे के जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी सरकार ने1 मई 2016को पीएम उज्ज्वला योजना की नींव रखी थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन दिए जाते हैं।

>> नवीनतम डेटा:आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई 2025 तक देश भर में करीब 10.33 करोड़ से अधिक मुफ्त उज्ज्वला कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। लाभार्थियों को रिफिल पर विशेष सब्सिडी भी दी जाती है।

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana)

देश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए23 सितंबर 2018को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत-पीएम जन आरोग्य योजना (PM-JAY) शुरू की गई थी। इसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है।

>> वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा अपडेट:11 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इस योजना का ऐतिहासिक विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को इसके दायरे में शामिल कर लिया है, चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी क्यों ना हो।

यदि आप बिहार या अन्य राज्यों में इन योजनाओं के विशेष शिविरों की जानकारी चाहते हैं, तो आपपीएम किसान, आयुष्मान और आवास योजना का लाभ? 17-18 जून खासलेख पढ़ सकते हैं।

अन्नदाता को सीधी आर्थिक मदद: जानिए कैसे पीएम किसान सम्मान नि

भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की समृद्धि के बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सीधे बैंक खातों में मदद पहुंचाने की योजना बनाई।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi)

देश के छोटे और सीमांत किसानों को खेती-किसानी के खर्चों और घरेलू जरूरतों के लिए सीधी वित्तीय सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने24 फरवरी 2019को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी।

>> आर्थिक सहायता का स्वरूप:इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की डायरेक्ट कैश

सहायता दी जाती है।

>> किस्त प्रणाली:यह राशि सरकार द्वारा 2,000-2,000 रुपए की तीन अलग-अलग किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना Status Check कर सकते हैं और Beneficiary List में अपना नाम देख सकते हैं।

संकट में बना सहारा: पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 कर

कोरोना महामारी के अभूतपूर्व संकट के दौरान देश के किसी भी गरीब परिवार को भूखा न सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक विशाल खाद्य सुरक्षा नेटवर्क तैयार किया, जो आज भी निरंतर जारी है।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)

वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के समय देश के गरीब व जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने26 मार्च 2020को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का शंखनाद किया था।

>> लाभार्थियों की संख्या:यह योजना देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को कवर करती है।

>> मुफ्त राशन का पैमाना:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले नियमित राशन के अलावा, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज (गेहूं चावल) प्रदान किया जाता है। इसने देश से भुखमरी और कुपोषण को मिटाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

हुनर को सम्मान और आत्मनिर्भरता: पीएम विश्वकर्मा योजना और पीए

अपने हालिया कार्यकाल में मोदी सरकार ने पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और आम नागरिकों के बिजली बिल को शून्य करने के लिए दूरदर्शी कदम उठाए हैं। हालांकि, इन योजनाओं के नाम पर होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बचना भी जरूरी है, जिसके बारे में आपसाइबर सरकार का घोटाला: कैसे सरकारी योजनाओं के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटालासे विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana)

देश के पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों, लोहारों, बुनकरों और अन्य श्रमसाध्य व्यवसायों से जुड़े लोगों को आधुनिक बाजार के

अनुकूल बनाने और वित्तीय सहायता देने के लिए मोदी सरकार ने17 सितंबर 2023को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी।

>> लोन और ट्रेनिंग:इस योजना के अंतर्गत कारीगरों को कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और बेहद कम ब्याज दर पर बिना गारंटी का लोन दिया जाता है।

>> वित्तीय प्रगति:सिरकार अब तक इस योजना के तहत 41,188 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 4.7 लाख से अधिक लोन कारीगरों और शिल्पकारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वितरित कर चुकी है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yoj

आम नागरिकों को महंगे बिजली बिलों से स्थायी राहत देने और देश को रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए15 फरवरी 2024को इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया था।

>> सब्सिडी का प्रावधान:इस योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल (Rooftop Solar Panel) लगवाने के लिए सरकार भारी सब्सिडी देती है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने पर अधिकतम 78,000 रुपए तक की सरकारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। इच्छुक नागरिक इसके लिए Apply Online कर सकते हैं।

निष्कर्ष: 11 वर्षों के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं का बढ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों का सफर देश के आम नागरिकों के सशक्तिकरण का गवाह रहा है। बैंकिंग व्यवस्था से अछूते करोड़ों लोगों को वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने से लेकर, आयुष्मान भारत के तहत मिलने वाले मुफ्त इलाज और पीएम सूर्यघर योजना के तहत मिल रही मुफ्त बिजली तक, हर नीति का केंद्र बिंदु देश का आम आदमी रहा है।

इन योजनाओं के माध्यम से न केवल देश का सामाजिक-आर्थिक ढांचा मजबूत हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम कसते हुए बिचौलियों की भूमिका को समाप्त किया गया है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का विस्तार और 2029 तक पीएम आवास योजना जैसी पहलों की निरंतरता यह दर्शाती है कि सरकार का विजन दीर्घकालिक और अंत्योदय की भावना से प्रेरित है। आगामी समय में ये नीतियां विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण धुरी साबित होंगी।

जनता के सवाल (FAQs)

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश के नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने वाली पीएम जनधन योजना के तहत अब तक कुल 56.38 करोड़ से अधिक शून्य बैलेंस खाते खोले जा चुके हैं।

11 सितंबर 2024 को किए गए नए विस्तार के तहत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के पात्र हैं, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो।

इस योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों को सरकार की तरफ से प्रति वर्ष कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपए की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अधिकतम 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।

गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने योजना की व्यापक सफलता को देखते हुए पीएम आवास योजना की अवधि को बढ़ाकर वर्ष 2029 तक कर दिया है।

18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना का खाता खोल सकता है। नियमित योगदान करने पर, 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति माह तक की निश्चित पेंशन मिलती है।

कोरोना काल में 26 मार्च 2020 को शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।